

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 19/2018

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थी:-
सरकार जरिये तहसीलदार रोहट		मोडाराम बनाम दौलाराम बावरी, निवासी रामपुरा तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

--: आदेश :-

दिनांक : 26.02.2019

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरुद्ध अप्रार्थी के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/79 रकबा 10 बीघा किस्म बा.सो. के नियम विरुद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/79 रकबा 10 बीघा किस्म बा.सो. जो गैर मुम्किन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन अप्रार्थी मोडाराम के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से बा.सो. कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरुद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 28.04.1976 के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 09.09.1976 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांक 08.05.1993 एवं 706 दिनांक 28.12.2010 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुम्किन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/79 रकबा 10 बीघा किस्म बा.सो. जो गैर मुम्किन नदी दर्ज थी, जिसका आवंटन अप्रार्थी मोडाराम पुत्र दौलाराम बावरी निवासी रामपुरा को आवंटन

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)



कमेटी ने अपने आदेश दिनांक 28.04.1976 के द्वारा किस्म परिवर्तन कर किया गया, उसमें अप्रार्थी मोडाराम ने प्रार्थना पत्र नियम 17(1-अ) राजस्थान सीलिंग कृषि नियम, 1973 के तहत एवं रूपा पुत्र जोराराम पिटल से सीलिंग के तहत अवाप्तसुदा भूमि खसरा नम्बर 366 में से 10 बीघा भूमि आवंटित करने हेतु पेश किया, लेकिन आवंटन कमेटी ने अप्रार्थी को खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी की भूमि में से अप्रार्थी को 10 बीघा भूमि किस्म परिवर्तित कर आवंटित कर दी एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 09.09.1976 स्वीकृत किया गया, जिसके द्वारा मोडा पुत्र दौला बावरी को गैर खातेदार दर्ज किया गया, इसके पश्चात जरिये ना.स. 444 दिनांक 08.05.1993 को अति. तहसीलदार रोहट द्वारा खातेदार दर्ज किया गया तथा तहसीलदार रोहट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 706 दिनांक 28.12.2010 के द्वारा मोडा पुत्र दौला का नाम मोडाराम पुत्र दौलाराम दर्ज किया गया। वक्त आवंटन/नियमन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थीगण के हक में किया गया आवंटन विधि विरुद्ध है तथा स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से आवंटन कमेटी के आवंटन ओदश दिनांक 28.04.1976 की पालना में ग्राम रामपुरा पटवार हल्का लालकी के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 09.09.1976 एवं उसके पश्चातवर्ती ना.स. 444 दिनांक 08.05.1993 तथा 706 दिनांक 28.12.2010 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप तहसीलदार, रोहट द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी मोडाराम पुत्र दौलाराम बावरी निवासी रामपुरा तहसील रोहट जिला पाली (राज.) के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा जो आवंटन किया गया उक्त आदेश दिनांक 28.04.1976 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 09.09.1976 एवं उसके पश्चातवर्ती ना.स. 444 दिनांक 08.05.1993 तथा 706 दिनांक 28.12.2010 को निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन कर बारानी अब्बल से पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सादर प्रेषित है।



(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली (राज.)